

Amar Ujala, 6th Feb, Pg 3.

समर्थन विश्व के कई देशों के नेताओं का भी मिल रहा है साथ

चौतरफा घिरे पचौरी के बचाव में उतरे प्रधानमंत्री

पेटीआई



नई दिल्ली में शुक्रवार को सतत विकास के 10वें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी से बातचीत करते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।

● एजेंसी

नई दिल्ली। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने को लेकर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की अपुष्ट खबरों के लिए आलोचना का शिकार बने आरके पचौरी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में पचौरी को उनके योगदान के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सम्मान और ख्याति मिली है, वह उसके हकदार है। उधर, जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन में शामिल विश्व के विभिन्न देशों के नेताओं ने भी पचौरी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में

कुछ गलती से ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े तथ्य नहीं बदल जाते। इन नेताओं में भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले के साथ ही नार्वे, यूनान और फिनलैंड के प्रधानमंत्री तथा किरिबाती के राष्ट्रपति शामिल हैं।

सिंह ने यहां दिल्ली सतत विकास के दसवें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आईपीसीसी की प्रक्रिया और उसके नेतृत्व में भारत को पूरा विश्वास है और वह इसका समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कोपेनहेगन समझौता

संयुक्त राष्ट्र की सहमति वाली जलवायु वार्ता का विकल्प नहीं है, लेकिन भारत इसकी सफलता के लिए काम करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में नौ करोड़ 90 लाख टन की कटौती करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक आम राय के अभाव पर खेद प्रकट करते हुए औद्योगिक देशों से कहा कि वे भविष्य के अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में पहल करें। उन्होंने विकसित देशों से यह भी कहा कि वे ग्रीन हाउस गैसों के संग्रह में अपनी भूमिका को और अधिक स्पष्टता से स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने देश के 120 अनुसंधान संस्थानों के जरिए जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक भारतीय नेटवर्क की स्थापना की है।

उन्होंने बताया कि भारत देहरादून में हिमालयन ग्लेशिओलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी मांगा। नोबेल पुरस्कार विजेता पचौरी को आईपीसीसी की 2007 की रिपोर्ट के उन कुछ पहलुओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार का 'गलत' उल्लेख किया गया है।

पीएम बोले

कोपेनहेगन समझौता
आईपीसीसी प्रक्रिया
का विकल्प नहीं

कार्बन उत्सर्जन में
9.9 करोड़ टन की
कटौती करेगा भारत